REVIEW OF RESEARCH
IMPACT FACTOR : 5.2331 (UIF) UGC APPROVED JOURNAL NO. 48514 ISSN: 2249-894X
VOLUME - 7 | ISSUE - 7 | APRIL - 2018

"उपभोक्ताओं पर वस्तु एवं सेवा कर का प्रभाव "

डॉ.राजू रैदास[1] , राजेन्द्र प्रसाद पटेल[2]
[1]अतिथि विद्वान (वाणिज्य) शास.महाविद्यालय उमरिया.
[2]अतिथि विद्वान (अर्थशास्त्र) शास.महाविद्यालय उमरिया.

प्रस्तावना :–

भारत के अप्रत्यक्ष कर शासन की सुधार प्रक्रिया 1986 में शुरू हुई थी, जिसमें विश्व वित्त प्रताप सिंह , राजीव गांधी की सरकार में वित्त मंत्री ने संशोधित मूल्य वर्धित कर की शुरुआत की थी। (एमओडीवीएटी) इसके बाद, प्रधान मंत्री पीनरसिम्हा राव .वी. और उनके वित्त मंत्री मनमोहन सिंह ने राज्य स्तर पर मूल्यवर्धित कर (वैटपर शीघ्र चर्चा शुरू (की। प्रधान मंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और उनकी आर्थिक सलाहकार समिति के बीच हुई एक बैठक के दौरान 1999 में एक एकल का प्रस्ताव रखा गया था और आरबीआई के तीन पूर्व राज्यपाल "(जीएसटी) माल और सेवा कर" आईजी पटेल , बिमल जालान और सी रंगराजन वाजपेयी ने पश्चिम बंगाल के वित्त मंत्री की अध्यक्षता असीम दासगुप्ता की जीएसटी मॉडल को डिजाइन करने के लिए एक समिति की स्थापना की।

देश में एक समान कराधान शासन शुरू करने के लिए, रवि दासगुप्ता समिति को बैक एंड टेक्नोलॉजी और लॉजिस्टिक्स बाद में जीएसटी नेटवर्क के रूप में जाना जाने लगा), या जीएसटीएन, 2017 मेंके रूप में स्थापित किया (गया था। 2002 में वाजपेयी सरकार ने कर सुधारों की सिफारिश करने के लिए विजय केलकर के तहत एक टास्क फोर्स का गठन किया था। 2005 में, केल्कर समिति ने 12 वीं वित्त आयोग द्वारा सुझाई गई जीएसटी को जारी करने की सिफारिश की थी।

2004 की लोकसभा चुनाव में बीजेपी की एनडीए सरकार की हार और कांग्रेस की अगुवाई वाली यूपीए सरकार के चुनाव के बाद, फरवरी 2006 में नए वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने भी इस पर काम जारी रखा और 1 अप्रैल 2010 को जीएसटी रोलआउट का प्रस्ताव दिया। हालांकि, 2010 में, तृणमूल कांग्रेस के साथ पश्चिम बंगाल में सीपीआई (एम) को सत्ता से बाहर कर दिया गया, असिम दासगुप्ता ने जीएसटी समिति के प्रमुख के रूप में इस्तीफा दे दिया। दासगुप्ता ने एक साक्षात्कार में स्वीकार किया कि कार्य का 80% कार्य किया गया था।

2014 लोकसभा चुनाव में , भारतीय जनता पार्टी- एनडीए सरकार सत्ता में निर्वाचित हुई, इस बार नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 15 वीं लोकसभा के परिणामी विघटन के साथ, जीएसटी विधेयक पुनः गठित करने के लिए स्थायी समिति - समाप्त हो गया। - द्वारा अनुमोदित मोदी सरकार के गठन के सात महीने बाद, नए वित्त मंत्री अरुण जेटली ने लोकसभा में जीएसटी विधेयक पेश किया, जहां भाजपा को बहुमत मिला। फरवरी 2015 में जेटली ने 1 अप्रैल 2017 को जीएसटी लागू करने की एक और समय सीमा तय की। मई 2016 में, लोकसभा ने संविधान संशोधन विधेयक पारित किया, जीएसटी के लिए मार्ग तैयार किया। हालांकि, कांग्रेस की अगुआई वाली विपक्ष ने टैक्सेशन से जुड़े विधेयक में कई बयानों पर असहमति के कारण जीएसटी विधेयक को फिर से राज्यसभा की चयन समिति को वापस भेज दिया। अंत में अगस्त 2016 में, संशोधन विधेयक पारित किया गया था। अगले 15 से 20 दिनों में, 18 राज्यों ने जीएसटी विधेयक को मंजूरी दी और राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने इसके लिए सहमति दी।

प्रस्तावित जीएसटी कानूनों की जांच के लिए 22 सदस्यीय समिति बनाई गई थी। राज्य और संघ राज्य जीएसटी कानून जम्मू और कश्मीर को छोड़कर भारत के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा पारित किए गए, 1

जुलाई 2017 से कर के चिकनी रोलआउट का मार्ग बनाते हुए। जम्मू और कश्मीर राज्य विधानमंडल ने इसे पारित कर दिया 7 जुलाई 2017 को जीएसटी अधिनियम, जिससे पूरे देश को एक एकीकृत अप्रत्यक्ष कर प्रणाली के तहत लाया गया है। सिक्योरिटीज की बिक्री और खरीद पर कोई जीएसटी नहीं होना था। यह सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स (एसटीटीद्वारा (शासित है।

जीएसटी का भारत में लागू होना :–

माल और सेवा कर 1 जुलाई 2017 को भारत के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी और भारत के प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्यरात्रि में शुरू किया था। संसद के केंद्रीय हॉल में आयोजित संसद के दोनों सदनों के एक ऐतिहासिक मध्यरात्रि)30 जून से 1 जुलाईसत्र का शुभारंभ किया गया था। (हालांकि इस सत्र में व्यापार और मनोरंजन उद्योग सहित हाईप्रोफाइल मेहमानों ने भाग लिया था-, जिसमें रतन टाटा शामिल थे , भविष्यवाणी की गई समस्याओं के कारण विपक्ष द्वारा इसका बहिष्कार किया गया था कि वह मध्य और निचले वर्ग के भारतीयों के लिए नेतृत्व करने के लिए बाध्य था। यह कुछ आधी रात के सत्रों में से एक है जो संसद द्वारा आयोजित किया गया है अन्य -15 अगस्त 1 9 47 को भारत की आजादी की घोषणा के रूप में हैं , और उस अवसर के रजत और स्वर्ण जयंती हैं। इसके प्रक्षेपण के बाद, जीएसटी दरों को कई बार संशोधित किया गया है, जो कि 18 जनवरी 2018 को नवीनतम है, जहां संघीय और राज्य वित्त मंत्रियों के एक पैनल ने 29 वस्तुओं और 53 सेवाओं पर जीएसटी दरों को संशोधित करने का फैसला किया।

कांग्रेस के सदस्यों ने जीएसटी प्रक्षेपण का बहिष्कार किया। वे तृणमूल कांग्रेस के सदस्यों, भारत के कम्युनिस्ट दलों और डीएमके से जुड़े हुए थे। पार्टियों ने रिपोर्ट किया कि वे जीएसटी और मौजूदा कराधान प्रणाली के बीच लगभग कोई अंतर नहीं पाया, यह दावा करते हुए कि सरकार केवल मौजूदा कराधान प्रणाली को पुन्ब्रांड करने की कोशिश कर : रही है। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि जीएसटी, आम दैनिक सामानों पर मौजूदा दरों को बढ़ाएगा जबकि लक्जरी सामानों की दरें कम कर दी जाएंगी, और कई भारतीयों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े, खासकर मध्य, निचला मध्य और गरीब वर्ग। भारत का जीएसटी मॉडल फ्रांस की कर प्रणाली पर आधारित है।

कर प्रकृति :–

जीएसटी एक मूल्य वर्धित कर है जो कि विनिर्माता से लेकर उपभोक्ता तक वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति पर एक एकल कर है। प्रत्येक चरण पर भुगतान किये गये इनपुट करों का लाभ मूल्य संवर्धन के बाद के चरण में उपलब्ध होगा जो प्रत्येक चरण में मूल्य संवर्धन पर जीएसटी को आवश्यक रूप से एक कर बना देता है। अंतिम उपभोक्ताओं को इस प्रकार आपूर्ति श्रृंखला में अंतिम डीलर द्वारा लगाया गया जीएसटी ही वहन करना होगा।

चुंगी, सेंट्रल सेल्स टैक्स (सीएसटी), राज्य स्तर के सेल्स टैक्स या वैट, एंट्री टैक्स, लॉटरी टैक्स, स्टैंप ड्यूटी, टेलिकॉम लाइसेंस फी, टर्नओवर टैक्स, बिजली के इस्तेमाल या बिक्री पर लगने वाले टैक्स, सामान के ट्रांसपोर्टेशन पर लगने वाले टैक्स इत्यादि अनेकों करों के स्थान पर अब यह एक ही कर लागू किया जा रहा है।

जीएसटी का प्रभाव :–

भारत में, हम वर्तमान में वस्तुओं और सेवाओं पर एक अप्रत्यक्ष प्रणाली के माध्यम से करों का भुगतान करते हैं। निर्माताओं वर्तमान में सरकार को इन करों का भुगतान करते हैं लेकिन लागत अंततः उपभोक्ताओं द्वारा वहन करती है। उदाहरण के तौर पर वैल्यू एडेड टैक्स (वैट), उत्पादित वस्तुओं पर उत्पाद शुल्क और सेवा कर जैसे करों को वर्तमान में केंद्रीय और राज्य सरकारों में विभिन्न कर अधिकारियों द्वारा प्रबंधित किया जाता है। करों की यह व्यवस्था प्रशासन को काफी जटिल बना सकती है।

भारत सरकार गुड्स एंड सर्विस टैक्स (जीएसटी) के माध्यम से अप्रत्यक्ष करों की इस प्रणाली को सरल बनाने की कोशिश कर रही है। यह माल के निर्माण, बिक्री, सेवा और उपभोग पर एक देशव्यापी कर होगा और मौजूदा कर

प्रणाली को बदल देगा। जीएसटी उपभोक्ताओं को वर्तमान प्रणाली के तहत लाभ देगा, उपभोक्ताओं को पहले से ही निर्माता द्वारा चुकाए गए करों पर कर का भुगतान करना होगा।

- इससे राज्यों के बीच बाधाएं दूर हो जाएंगी जो माल के परिवहन को अधिक कर कुशल बनाती हैं।
- कर भी आवश्यक चेकपॉइंट की संख्या कम कर देगा और साथ ही पारगमन के समय में भी सुधार करेगा।

शेयर बाजार अक्सर लोगों के व्यवहार से प्रभावित होता है वर्तमान में, जीएसटी के संबंध में बहुत उत्साह है। हालांकि, जब तक कर की दरें नाटकीय रूप से बदलती न हों, अप्रत्यक्ष कर परिवर्तन को हटाने से मूलभूत दावों को वास्तव में पता नहीं हो सकता है अधिक उपभोज्य आय के साथ उपभोक्ताओंका व्यवहार भी अनुमान नहीं लगाया जा सकता है और इसलिए यह उचित है कि वर्तमान उत्साह को बहुत गंभीरता से न लेना चाहिए। इसलिए जब कर सुधार लंबे समय में फायदेमंद हो सकते हैं, निवेश निर्णय लेने में सतर्क होना चाहिए। कंपनी का समग्र मूल्यांकन जीएसटी और इसके व्यापार नीतियों, पिछले प्रदर्शन, मुख्य दक्षता और व्यवसाय के लिए भुगतान की गई कीमतों की तुलना में कई कारकों पर निर्भर करता है। इक्विटी के वैल्यूएशन पर जीएसटी का प्रभाव वर्तमान में अनिश्चित है।

जीएसटी के लाभ :– व्यापार और उद्योग के लिए

- आसान अनुपालन, पारदर्शिता: एक मजबूत और व्यापक सूचना प्रौद्योगिकी प्रणाली भारत में जीएसटी व्यवस्था की नींव होगी इसलिए पंजीकरण, रिटर्न, भुगतान आदि जैसी सभी कर भुगतान सेवाएं करदाताओं को ऑनलाइन उपलब्ध होंगी, जिससे इसका अनुपालन बहुत सरल और पारदर्शी हो जायेगा।
- कर दरों और संरचनाओं की एकरूपता: जीएसटी यह सुनिश्चित करेगा कि अप्रत्यक्ष कर दरें और ढांचे पूरे देश में एकसमान हैं। इससे निश्चिंतता में तो बढ़ोतरी होगी ही व्यापार करना भी आसान हो जाएगा। दूसरे शब्दों में जीएसटी देश में व्यापार के कामकाज को कर तटस्थ बना देगा फिर चाहे व्यापार करने की जगह का चुनाव कहीं भी जाये।
- करों पर कराधान (कैसकेडिंग) की समाप्ति- मूल्य श्रृंखला और समस्त राज्यों की सीमाओं से बाहर टैक्स क्रेडिट की सुचारू प्रणाली से यह सुनिश्चित होगा कि करों पर कम से कम कराधान हों। इससे व्यापार करने में आने वाली छुपी हुई लागत कम होगी।
- प्रतिस्पर्धा में सुधार – व्यापार करने में लेन-देन लागत घटने से व्यापार और उद्योग के लिए प्रतिस्पर्धा में सुधार को बढ़ावा मिलेगा।
- विनिर्माताओं और निर्यातकों को लाभ – जीएसटी में केन्द्र और राज्यों के करों के शामिल होने और इनपुट वस्तुएं और सेवाएं पूर्ण और व्यापक रूप से समाहित होने और केन्द्रीय बिक्री कर चरणबद्ध रूप से बाहर हो जाने से स्थानीय रूप से निर्मित वस्तुओं और सेवाओं की लागत कम हो जाएगी। इससे भारतीय वस्तुओं और सेवाओं की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में होने वाली प्रतिस्पर्धा में बढ़ोतरी होगी और भारतीय निर्यात को भी बढ़ावा मिलेगा। पूरे देश में कर दरों और प्रक्रियाओं की एकरूपता से अनुपालन लागत घटाने में लंबा रास्ता तय करना होगा।

केन्द्र और राज्य सरकारों के लिए लाभ :–

- सरल और आसान प्रशासन - केन्द्र और राज्य स्तर पर बहुआयामी अप्रत्यक्ष करों को जीएसटी लागू करके हटाया जा रहा है। मजबूत सूचना प्रौद्योगिकी प्रणाली पर आधारित जीएसटी केन्द्र और राज्यों द्वारा अभी तक लगाए गए सभी अन्य प्रत्यक्ष करों की तुलना में प्रशासनिक नजरिए से बहुत सरल और आसान होगा।
- कदाचार पर बेहतर नियंत्रण – मजबूत सूचना प्रौद्योगिकी बुनियादी ढांचे के कारण जीएसटी से बेहतर कर अनुपालन परिणाम प्राप्त होंगे। मूल्य संवर्धन की श्रृंखला में एक चरण से दूसरे चरण में इनपुट कर क्रेडिट कर सुगम हस्तांतरण जीएसटी के स्वरूप में एक अंत:निर्मित तंत्र है, जिससे व्यापारियों को कर अनुपालन में प्रोत्साहन दिया जाएगा।

- अधिक राजस्व निपुणता – जीएसटी से सरकार के कर राजस्व की वसूली लागत में कमी आने की उम्मीद है। इसलिए इससे उच्च राजस्व निपुणता को बढ़ावा मिलेगा।

उपभोक्ताओं के लिए लाभ :–

- वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य के अनुपाती एकल एवं पारदर्शी कर – केन्द्र और राज्यों द्वारा लगाए गए बहुल अप्रत्यक्ष करों या मूल्य संवर्धन के प्रगामी चरणों में उपलब्ध गैर-इनपुट कर क्रेडिट के कारण आज देश में अनेक छिपे करों से अधिकांश वस्तुओं और सेवाओं की लागत पर प्रभाव पड़ता है। जीएसटी के अधीन विनिर्माता से लेकर उपभोक्ताओं तक केवल एक ही कर लगेगा, जिससे अंतिम उपभोक्ता पर लगने वाले करों में पारदर्शिता को बढ़ावा मिलेगा।
- समग्र कर भार में राहत – निपुणता बढ़ने और कदाचार पर रोक लगने के कारण अधिकांश उपभोक्ता वस्तुओं पर समग्र कर भार कम होगा, जिससे उपभोक्ताओं को लाभ मिलेगा।

भारत में जीएसटी की दरें :–

जीएसटी काउंसिल ने चार तरह के कर निर्धारित किये हैं ये 5, 12, 18 एवं 28 प्रतिशत | हालांकि बहुत सी चीजों को जीएसटी से छूट दी गई है उन वस्तुओं पर कोई भी कर नहीं लगेगा या जीएसटी नहीं लगेगा जबकि लग्जरी एवं महंगे सामान पर जीएसटी के अलावा सेस भी लगेगा। सरकार के अनुसार इसमें से 81 प्रतिशत चीजें जीएसटी की 18 प्रतिशत की श्रेणी तक आएंगी |

आदर्श स्थिति में इस व्यवस्था में समस्त कर एक ही दर पर लगाए जाने चाहिएँ, किन्तु भारत में राज्य व केन्द्र तथा एक ही वस्तु या सेवा पर भिन्नभिन्न राज्यों में भिन्न दरें आदि होने से- प्रारम्भ में ४ दरें निर्धारित की गईं ताकि वर्तमान राजस्व में अधिक अंतर न पड़े। ये चार दरें 5%, 12%, 18% तथा 28% हैं। आवश्यक वस्तुओं जैसे कि दूध, लस्सी, दही, शहद, फल एवं सब्जियां, आटा, बेसन, ताजा मीट, मछली, चिकन, अंडा, ब्रेड, प्रसाद, नमक, बिंदी, सिंदूर, स्टांप, न्यायिक दस्तावेज, छपी पुस्तकें, समाचार पत्र, चूड़ियाँ और हैंडलूम आदि वस्तुओं पर जीएसटी नहीं लगेगा। २० लाख से कम की वार्षिक बिक्री वाले व्यापारियों को इस कर व्यवस्था से छूट दी गई है।

निष्कर्ष :–

1. अब लोगों के स्वास्थ्य के लिए अनुकूल या हानिकारक सामान 'कर टैक्स' या 'निवारक कर' के रूप में जाना जाता है। इस प्रकार तंबाकू और तम्बाकू संबंधित वस्तुओं को सिगरेट आदि की लागत को दंडित किया जाता है। केरल राज्य ने पिज्जा आदि पर 'फेट टैक्स' शुरू कर दिया है। यह लोगों को पीड़ितों को ऐसे आदतों से गिरने से रोकने और उन्हें रोकने के लिए भी था। यह सरकार की एक सामाजिक-स्वास्थ्य जिम्मेदारी निभाता है। अब वे अतिरिक्त कर से बाहर हैं और किसी भी अन्य सामान के रूप में कर लगाया जाता है। यह उच्च सामाजिक स्वास्थ्य लागत के लिए मार्ग प्रशस्त करेगा, जो कि आगे के कराधान को बढ़ाने में मदद करेगा।
2. सरकार ने टैक्स दर के लिए किसी भी उच्च सीमा को करने के लिए सहमत नहीं किया है। यह बहुत स्पष्ट रूप से दिखाता है कि करों की उच्च दरों की हमेशा संभावना होती है यह उन लोगों के तर्कों को हटा देगा जो कहते हैं कि जीएसटी अच्छा है।
3. जीएसटी सभी प्रकार के कराधान से दूर नहीं होता है या नहीं बदलता है।यह सिर्फ एक मुट्ठी या कम अलग करों को मिला दिया है और इन्हें एक ही नाम से जोड़ दिया है।
4. सेवा कर समाहित है, लेकिन सभी सेवाओं को माल के समान जीएसटी में शामिल किया गया है। अब जो क्षेत्र शामिल नहीं हैं, वे पहले से बचने की कोशिश का विरोध कर सकते हैं, लेकिन अगर मजबूर ही अंतिम सेवा उपयोगकर्ता पर बोझ को हस्तांतरित करेगा। इसलिए असल में जीएसटी की आड़ में सेवा कर के तहत आने वाले और अधिक आइटम होंगे।

5. जीएसटी के समर्थकों का दावा है कि कर मामलों पर मुकदमेबाजी कम हो जाएगी। वह सत्य नहीं है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि कार्यान्वयन की शर्तों को कैसे स्पष्ट रूप से परिभाषित किया जाता है और इसका अनुवाद किया जाता है। हमारे नियमों और नियमों के 'आधिकारिक' या जार्गन और खंड-इन-क्लाउज शब्दों के अनुभव से, मैं उस आशावादी नहीं हूं। कानूनी क्षेत्र ही एक होगा जो कि मुकदमेबाजी शुरू कर सकता है, जैसा कि सही तरीके से व्याख्या किए जाने पर अब वे सेवा कर के तहत भी आते हैं।
6. सर्विस सेक्टर्स सेवा लागतों के प्रमुख हिस्से को प्रतिपूर्ति या राजस्व व्ययों आदि के रूप में टालकर टैक्स दायित्व से बचने या कम करने का प्रयास करेंगे, जिसे वापस मिल सकता है और प्राप्त कर छूट प्राप्त कर सकते हैं। जीएसटी द्वारा सेवा क्षेत्र से उच्च कर राजस्व की उम्मीद को हरा सकता है।
7. मुझे लगता है कि संभव अनुकूल अंक हैं (ए) ई वाणिज्य को बढ़ावा मिलेगा और अधिक सम्मान गाह्यलांकि, चूंकि ऑनलाइन खरीदारी आम तौर पर दिन-प्रति-दिन वस्तुओं में नहीं होती है, आम आदमी इससे ज्यादा कुछ नहीं ले सकता है। इसके अलावा, इस दृश्य को बड़े बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा नियंत्रित किया जाता है।
8. कर मशीनरी के लिए थोड़ा और आसान होगा। यह सरकार के लिए है, आम आदमी के लिए नहींखुदरा विक्रेताओं को समान औपचारिकताओं के साथ जारी रखना होगा, हालांकि पहले के नाम और रूपों में
9. जीएसटी में पेट्रोलियम उत्पादों को शामिल करना तेल कंपनियों के लिए वरदान साबित होगा, जो मुख्य रूप से निजी कंपनियों को जाता है। थॉमस, जिन्होंने लागत कम नहीं किया था, जब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल की कीमतें अधिकतर आधे से गिर गई हैं, तो टैक्सिया तंत्र में एक छोटे कॉस्मेटिक बदलाव की लागत को कम करने की उम्मीद नहीं की जा सकती। इससे वास्तव में अधिक महंगी वृद्धि होगी।
10. जैसा कि मूल्य नियंत्रण नहीं है वहां जीएसटी निर्माताओं या प्रदाताओं को एक्साइज, सर्विस टैक्स आदि से प्राप्त अतिरिक्त लाभ लेने से नहीं रोकेगा। इस प्रकार मेरा अंतिम अनुमान यह है कि जीएसटी कॉर्पोरेट मैन्युफैक्चरर्स, ट्रेडर्स और सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए फायदेमंद होगा ।यह विशेष रूप से 'मेक इन इंडिया' के संबंध में निवेश लाने की आवश्यकता से बाहर आ गया है क्योंकि एफडीआई निवेशकों को संकुचन और लाभ की आवश्यकता होती है। आम आदमी के लिए कोई भी उद्देश्य या उद्देश्य का उद्देश्य भी नहीं है।
11. एकमात्र प्रार्थना यह है कि आम आदमी को बदतर नहीं होने दें, जो पहले से ही पीड़ित है और सरकार के असली रंग को रेल टिकटों में भी एक रुपये को कम करने की कोशिश नहीं कर रही है, बल्कि रेलवे को भी एक लालची वाणिज्यिक कॉरपोरेट इकाई बना रही है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :–

1. नव भारत पत्रिका वर्ष 2017
2. द इकोनॉमिक टाइम्स , 2017
3. द टाइम्स ऑफ इंडिया , 4 जुलाई 2017
4. द हिंदू बिजनेस लाइन, 25 जनवरी 2018
5- www.google.com/wikipedia.com

डॉ.राजू रैदास
अतिथि विद्वान (वाणिज्य) शास.महाविद्यालय उमरिया.

राजेन्द्र प्रसाद पटेल
अतिथि विद्वान (अर्थशास्त्र) शास.महाविद्यालय उमरिया.